



संदर्भ: सं. राबैं. डीएफआईबीटी/4434 – 4814/डीएफआईबीटी-23/2021-22

23 सितंबर 2021

परिपत्र सं. 185/ डीएफआईबीटी- 08/2021

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी राज्य सहकारी बैंक / सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

<p>ग्रामीण सहकारी बैंकों में चेक आधारित लेन-देन हेतु ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत पॉजिटिव पे सिस्टम को कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय सहायता</p>	<p>Financial support for implementing Positive Pay System under Financial Inclusion Fund (FIF) to RCBs for enhancing customer security for cheque based transactions</p>
<p>भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत दिनांक 01 जनवरी 2021 से की गई है। दिनांक 25 सितंबर 2020 के परिपत्र सं. डीपीएसएस. सीओ.आरपीपीडी.सं.309/0.07.005/2020-21 के माध्यम से रु.50,000/- या उससे अधिक राशि के चेक आधारित लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों के लिए यह सिस्टम लागू किया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) से चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी क्लियरिंग के लिए चेक जमा करता है और प्रस्तुत चेक की तुलना ग्राहक के विवरण के साथ की जाती है अर्थात् प्राप्तकर्ता का नाम, चेक की तिथि, चेक नंबर और राशि, आदि से संबंधित जानकारी पॉजिटिव पे सिस्टम के माध्यम से प्रदान की जाती है।</p>	<p>The Positive Pay System has been introduced by Reserve Bank of India w.e.f. 01 January 2021 vide their Circular No. DPSS. CO. RPPD. No.309/0.07.005/2020-21 dated 25 September 2020 to enhance the safety of cheque based transactions of Rs.50,000/- and above, applicable to all banks including StCBs and DCCBs. The Positive Pay System (PPS) enables an additional security layer to the cheque clearing process, where the beneficiary submits the cheque for clearing and the presented cheque details are compared with the details i.e. name of the payee, date of the cheque, cheque number and amount, etc. provided through Positive Pay System.</p>

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विभाग

Department of Financial Inclusion & Banking Technology

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2653 0024 • फैक्स : +91 22 2653 0150 • ई-मेल : dfibt@nabard.org

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2653 0024 • Fax : +91 22 2653 0150 • E-mail : dfibt@nabard.org

<p>2. ग्रामीण सहकारी बैंकों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, पीपीएस के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, वित्तीय समावेशन निधि के सलाहकार बोर्ड ने ग्रामीण सहकारी बैंकों में पीपीएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का विवरण निम्नानुसार है:</p> <p>i) योजना: इस योजना का नाम “ग्रामीण सहकारी बैंकों में चेक आधारित लेन-देन हेतु ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत पॉजिटिव पे सिस्टम को कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय सहायता.” है।</p> <p>ii) लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम सुविधा के कार्यान्वयन हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करना है।</p> <p>iii) पात्र संस्थाएं: सभी लाइसेन्स प्राप्त ग्रामीण सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) जिन्होंने कोर बैंकिंग सोल्यूशंस लागू किया है और पहले से ही पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर चुके हैं अथवा लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है ऐसी संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।</p> <p>iv) अनुदान की सीमा: प्रत्येक ग्रामीण सहकारी बैंक के लिए रु.5.00 लाख की सीमा के अधीन, वास्तविक व्यय के 90% की सीमा तक प्रतिपूर्ति के आधार पर एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।</p> <p>v) सहायता के घटक: सहायता के घटक बैंक के पास उपलब्ध सभी बैंकिंग चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, मोबाइल एप्प, एटीएम, आदि. में पॉजिटिव पे प्रणाली प्रदान करने की दिशा में एक वर्ष के लिए</p>	<p>2. Based on the request received from RCBs, for providing support for implementation of PPS, the Advisory Board of FIF has approved the scheme for providing grant assistance for implementation of PPS in RCBs. The details of the scheme are as under:</p> <p>i) Scheme: The scheme is named “Financial support for implementing Positive Pay System under FIF to RCBs for enhancing customer security for cheque based transactions”.</p> <p>ii) Objective: The objective of the scheme is to reimburse the expenditure incurred by RCBs towards implementation of Positive Pay System facility.</p> <p>iii) Eligible Institutions: All licensed Rural Cooperative Banks (StCBs and DCCBs) that have implemented Core Banking Solution (CBS) and already implemented Positive Pay System facility or are in the process of implementing the same are eligible to avail assistance under the scheme.</p> <p>iv) Extent of Support: One time support shall be provided on reimbursement basis to the extent of 90% of actual expenditure incurred, subject to the limit of Rs.5.00 lakh per RCB.</p> <p>v) Components of support: The components of support are one-time software application development, implementation cost and operational expenditure including AMC for one year towards providing Positive Pay System</p>
--	--

<p>एएमसी सहित एकबार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कार्यान्वयन लागत और परिचालन व्यय शामिल हैं.</p> <p>vi) जागरूक करना: ग्रामीण सहकारी बैंकों को पॉजिटिव पे प्रणाली योजना के बारे विविध माध्यमों अपने ग्राहकों को जैसे कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शाखा/कार्यालय में डिस्प्ले बोर्ड लगाकर, वेब साइट के माध्यम से, एटीएम, मोबाइल डेमो वैन आदि. के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है.</p> <p>vii) अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :</p> <p>क. बैंक नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों का दिनांक 23 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. 105/डीएफआईबीटी-04/2019 के अनुबंध III और IV के अनुसार मंजूरी और दावे के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें.</p> <p>ख. वे बैंक जो इस योजना के अंतर्गत पहली बार वित्तीय समावेशन निधि की अनुदान सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें दिनांक 20 मार्च 2018 के परिपत्र सं. 52/डीएफआईबीटी-05/ 2018 के अनुसार नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) निष्पादित करना होगा.</p>	<p>across all banking channels available with the bank viz., internet banking, SMS, mobile App, ATM, etc.</p> <p>vi) Awareness Creation: RCBs implementing the scheme need to create awareness about PPS as part of their customer education process through various means i.e. financial literacy program, display in the branch/office, website, ATMs, Mobile Demo Vans, etc.</p> <p>vii) Procedure to be followed by banks to avail grant support:</p> <p>a. Banks may submit the proposal for sanction and claim as per Annexure – III and IV of Circular No.105/DFIBT-04/2019 dated 23 April 2019 to the concerned Regional Office of NABARD.</p> <p>b. Banks, which are seeking FIF grant under the scheme for the first time, may execute a Memorandum of Agreement with NABARD as per Circular No. 52/ DFIBT-05/ 2018 dated 20 March 2018.</p>
---	--

भवदीया

हस्ता/-

(आर शेरिंग)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2020-21/41

DPSS.CO.RPPD.No.309/04.07.005/2020-21

September 25, 2020

The Chairman and Managing Director / Chief Executive Officer
All Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks /
Urban Co-operative Banks / State Co-operative Banks /
District Central Co-operative Banks / Local Area Banks / Payment Banks /
Small Finance Banks / National Payments Corporation of India

Madam / Dear Sir,

Positive Pay System for Cheque Truncation System

Please refer to the Statement on Developmental and Regulatory Policies dated August 6, 2020 wherein Reserve Bank of India (RBI) had announced introduction of Positive Pay System for Cheque Truncation System (CTS).

2. The concept of Positive Pay involves a process of reconfirming key details of large value cheques. Under this process, the issuer of the cheque submits electronically, through channels like SMS, mobile app, internet banking, ATM, etc., certain minimum details of that cheque (like date, name of the beneficiary / payee, amount, etc.) to the drawee bank, details of which are cross checked with the presented cheque by CTS. Any discrepancy is flagged by CTS to the drawee bank and presenting bank, who would take redressal measures.

3. National Payments Corporation of India (NPCI) shall develop the facility of Positive Pay in CTS and make it available to participant banks. Banks, in turn, shall enable it for all account holders issuing cheques for amounts of ₹50,000 and above. While availing of this facility is at the discretion of the account holder, banks may consider making it mandatory in case of cheques for amounts of ₹5,00,000 and above.

4. Only those cheques which are compliant with above instructions will be accepted under dispute resolution mechanism at the CTS grids. Member banks may implement similar arrangements for cheques cleared / collected outside CTS as well.

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400001

फोन Tel: (91-22) 2260 1000; फैक्स Fax: (91-22) 2265 9566; ई मेल-e-mail : cgmdpssco@rbi.org.in

Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, 14th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

5. Banks are advised to create adequate awareness among their customers on features of Positive Pay System through SMS alerts, display in branches, ATMs as well as through their web-site and internet banking.

6. Positive Pay System shall be implemented from January 01, 2021.

7. This directive is issued under Section 10 (2) read with Section 18 of Payment and Settlement Systems Act, 2007 (Act 51 of 2007).

Yours faithfully

(P Vasudevan)
Chief General Manager